ग्रामीण तय करेंगे गांव की योजना

26 से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट, जॉबकार्डधारियों का होगा सर्वे, सूबे के 22 जिलों में छह माह तक चलेगा कार्यक्रम, बनेगी विस्तृत सूची

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

मनरेगा की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में जनभागीदारी बढ़ेगी। ग्रामीणों से यह पूछा जाएगा कि वे अपने गांवों में कौन सी योजना चाहते हैं। राज्य में करीब दो करोड़ 20 लाख ग्रामीण परिवार हैं जिनसे स्कीमों के बारे में पूछा जाएगा। मनरेगा के तहत मुख्य रूप से नहर की खुदाई, तालाब का निर्माण, पौधारोपण और मिट्टी की कटाई से संबंधित अन्य तरह का काम हो रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग ने तय किया है कि 26 जनवरी से पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत जॉबकार्डधारियों का सर्वे शुरू होगा। केन्द्र सरकार के संगठन नेहरू युवा केन्द्र (एनवाईके) के माध्यम से 22 जिलों में छह माह तक यह कार्यक्रम चलेगा। 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्त होगा। सर्वे के लिए एनवाईके के सदस्यों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है।

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजधानी के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में विभागीय मंत्री नीतीश मिश्र की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) की बैठक हुई जिसमें मनरेगा के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव

शुक्रवार को एएन सिन्हा संस्थान में ग्रामीण विकास विभाग की कार्यशाला को संबोधित करते ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव संतोष मैथ्यू। कार्यशाला में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्र भी उपस्थित थे। • हिन्दुस्तान

डायरेक्टर डॉ.खालिद हसन खान भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि जॉबकार्डधारियों के सर्वे के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। इसके तहत 22 जिलों के 220 प्रखण्डों के 8800 गांवों में सर्वे होगा। परिवारों से पूछा जाएगा कि उनका जॉब कार्ड बना है या नहीं। यह भी पूछा जाएगा कि वे काम कब चाहते हैं। पारिवारिक सर्वेक्षण के लिए विभाग ने 'काम की मांग का वार्षिक कैलेंडर और जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन प्रपत्र तैयार किया गया है। साथ ही योजना की पहचान के लिए भी प्रपत्र विकसित किया गया है। एनवाईके के कार्यकर्ता और एनवाईके युवा मंडल के सदस्य पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत पहले महीने में गांव के सभी परिवारों को घर-घर जाकर दिए गए प्रपत्र में सूचना जुटाएंगे।

जिन 22 जिलों में होगा सर्वे

बेगूसराय, बांका, वैशाली, नवादा, मधेपुरा, रोहतास, नालंदा, छपरा, अररिया, सीवान, सुपौल, जमुई, भागलपुर, जहानाबाद, किशनगंज, बक्सर, खगड़िया, गोपालगंज, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर

सर्वे की तैयारी

10-20 जनवरी : जिला स्तर पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। इसमें एनवाईके के प्रखण्ड स्तर के दो-दो वॉलेन्टियर भाग लेंगे। ट्रेनिंग मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी देंगे।

15-25 जनवरी : प्रखण्ड स्तर पर चिह्नित गांवों में स्थित मंडल के सदस्यों व पीआरएस की दो दिनों की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग संबंधित प्रखण्ड के कार्यक्रम पदाधिकारी देंगे।

26 जनवरी : एनवाईके के वॉलेन्टियर और एनवाईके यूथ क्लब के सदस्य गांवों में कार्यक्रम की शुरूआत जनसभा में करेंगे। इसमें मनरेगा के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और मनरेगा के मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे।

'पंचायत रोजगार सेवकों का स्थान सुनिश्चित करें'

पटना। जॉबकार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए अब भटकना नही होगा। सरकार यह व्यवस्था कर रही है जिसके तहत पंचायत रोजगार सेवकों के बैठने की एक निश्चित जगह तय कर दी जाए। ताकि वहां जाकर मजदूर जॉबकार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। यह आम शिकायत रही है कि जॉब कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को इधर से उधर भटकना पड़ता है।

ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने सभी उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) को अगले दस दिनों में पंचायत रोजगार सेवकों के बैठने के लिए जगह सुनिश्चित करने को कहा है। शुक्रवार को को ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह भी कहा गया कि इंदिरा आवास योजना के तहत सिर्फ लाभार्थियों को राशि उपलब्ध कराने से काम नही चलेगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि समय पर उनका मकान बनकर तैयार हो जाए। अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास के लक्ष्य को पूरा करने के साथ-साथ बैकलॉग को भी समाप्त करने को कहा गया। इस वर्ष 7 लाख 58 हजार आवास का लक्ष्य है। जबकि करीब तीन लाख आवास बैकलॉग के हैं।